RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक
वर्ष : 01
अंक : 276
दि. 07.02.2026, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

शिक्षकों को अपनी गति छात्रों से बस एक कदम आगे रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 के दौरान छात्रों से बातचीत की

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 9वें परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) के दौरान छात्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर परीक्षा के प्रति जागरूक छात्रों के साथ अनौपचारिक संवाद किया।

आपकी शैली, आपकी गति

गुजरात के एक छात्र ने पूछा कि माता-पिता तो बच्चों की चिंता करते हैं और शिक्षक उनका समर्थन करते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब शिक्षक एक अध्ययन पद्धति सुझाते हैं, माता-पिता दूसरी पर जोर देते हैं, और छात्र अलग-अलग पद्धति अपना लेते हैं, जिससे वे इस बात को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन सी पद्धति सही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी लोग उन्हें अलग-अलग सलाह देते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह घर में भाई-बहनों के खान-पान के तरीके अलग-अलग होते हैं—कुछ सब्जियों से शुरूआत करते हैं, कुछ दाल से, कुछ सब कुछ मिलाकर—हर किसी का अपना तरीका होता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आनंद अपनी पद्धति का पालन करने में ही मिलता है। श्री मोदी ने समझाया कि कुछ लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ सुबह जल्दी, और हर किसी की अपनी लय होती है। उन्होंने बेईमानी के प्रति आगाह करते हुए बताया कि कैसे कुछ छात्र अपनी माताओं से कहते हैं कि वे सुबह पढ़ेंगे लेकिन फिर पढ़ते नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को अपनी पद्धति पर भरोसा करना चाहिए, सुझावों को ध्यान से सुनना चाहिए और सुधार केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही करने चाहिए, न कि केवल इसलिए कि कोई और ऐसा कहता है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 'परीक्षा पे चर्चा' शुरू की थी, तब एक पद्धति थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने उसमें सुधार किया, यहां तक कि विभिन्न राज्यों में सत्र आयोजित किए, प्रारूप में बदलाव किया लेकिन मूल सिद्धांतों को बरकरार रखा।

छात्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री का स्वभाव बहुत ही मिलनसार है और वे आसानी से उनके साथ घुलमिल जाते हैं। उन्होंने समझाया कि सभी को अलग-अलग तौर-तरीकों को सुनना चाहिए, उनमें से प्रत्येक से अच्छे गुण लेने चाहिए, अपने स्वयं के गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और धीरे-धीरे उन्हें मजबूत करना चाहिए।

प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान, एक अन्य छात्र ने पूछा कि अक्सर छात्र स्कूल या शिक्षकों की गति से तालमेल नहीं बिठा पाते और छूटे हुए पाठों को पूरा करने की कोशिश में वे आगे के अध्यायों

से भटक जाते हैं और पिछड़ जाते हैं। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों को अपनी गति छात्रों से बस एक कदम आगे रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि लक्ष्य पहुंच के भीतर हो, लेकिन इतना आसान न हो कि उसे हासिल करना असंभव हो। जब छात्र ने एग्जाम वॉरियर मंत्र 26, "लक्ष्य पहुंच के भीतर होना चाहिए, किंतु आसानी से पहुंच योग्य भी ना हो," को याद दिलाया, तो प्रधानमंत्री ने उसकी इस बात की सराहना की। उन्होंने समझाया कि अगर शिक्षक पचास कदम आगे बढ़ जाते हैं, तो छात्र हार मान लेंगे, लेकिन जिस तरह एक किसान खेत जोतता है, उसी तरह शिक्षकों को छात्रों के मन को जोतना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों को प्रत्येक सप्ताह पढ़ाए जाने वाले अध्यायों की घोषणा पहले से कर देनी चाहिए, ताकि छात्र पाठ से पहले पढ़ना, प्रश्न पूछना या ऑनलाइन खोज करना शुरू कर सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब वास्तविक शिक्षण शुरू होता है, तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, समझ गहरी होती है और एकाग्रता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अध्याय बहुत रोचक है, तो छात्र और भी अधिक जानने की इच्छा रखेंगे, जिससे पुनरावलोकन अधिक प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक सरल विधि है। उन्होंने पूछा कि क्या इससे शिक्षक की गति की समस्या बनी रहेगी? जब छात्र ने हां में उत्तर दिया, तो श्री मोदी ने सुधार करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि छात्र अब पीछे छूट जाने का अहसास नहीं करेंगे, क्योंकि वे शिक्षक से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, 'पहले मन को विकसित करें, फिर उसे जोड़ें, और फिर अध्ययन के विषयों को व्यवस्थित करें। आप हमेशा छात्रों को सफल पाएंगे।' छात्रों ने कहा कि हर किसी को प्रधानमंत्री के साथ आमने-सामने बैठकर प्रश्न पूछने और बातचीत करने का अवसर नहीं मिलता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें शिक्षकों से दो कदम पीछे रहने के बजाय दो कदम आगे रहने की सलाह दी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे कभी पीछे न रह जाएं।

एक संगीतमय क्षण

सिक्किम की एक छात्रा ने बताया कि उसने तीन भाषाओं—हिन्दी, नेपाली और बंगाली—में 'हमारा भारत भूमि' शीर्षक से एक देशभक्ति गीत रचा है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या उसे कविता लिखना पसंद है, और उसकी पुष्टि पर उसे कविता सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने राष्ट्र की एकता—एक भारत, श्रेष्ठ भारत—की बात को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया है। इसके बाद श्री मोदी ने एक अन्य छात्रा, मानसी को गाने के लिए कहा। मानसी ने अपनी माता द्वारा रचित एक गीत प्रस्तुत किया, जो विद्यार्थियों को समर्पित था। प्रधानमंत्री ने उसकी प्रशंसा की और उसे अपनी माता को अपनी ओर से बधाई देने के लिए कहा। छात्रा ने बताया कि वह एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती है, जिसके फेसबुक पर 1.5 लाख फॉलोअर हैं। प्रधानमंत्री ने आश्चर्य और प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं से मिलना गर्व की बात है।

श्री मोदी ने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए बताया कि उन्होंने असम के गमोंसा से उनका अभिवादन किया है, जिसे वे अपना सबसे प्रिय मानते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया

संक्षिप्त समाचार

युवा वकीलों को स्टाइपेंड योजना

भारतीय बार काउंसिल द्वारा बताया गया है कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने राज्य सरकार की योजनाओं, राज्य बार काउंसिल के कल्याण तंत्र

और/या बार एसोसिएशन के संरचित कार्यक्रमों के माध्यम से जूनियर अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड और/या वित्तीय सहायता के उपाय शुरू किए हैं। महाराष्ट्र के संबंध में, किसी राज्यव्यापी स्टाइपेंड योजना के लिए सामान्यतः राज्य बार काउंसिल के स्तर पर एक कार्यान्वयन ढांचे की आवश्यकता होगी और/या राज्य सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम, जिसमें बजटीय सहायता, पात्रता मानदंड, सत्यापन और ऑडिट शामिल हों।

तमिलनाडु में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता- श्री नड्डा

नकली उर्वरकों के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई

(जीएनएस)।

भारत सरकार ने पुष्टि की है कि खरीफ 2025 और मौजूदा रबी 2025-26 मौसम के दौरान तमिलनाडु में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस (ठढङर) सहित प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है ।

वर्तमान रबी 2025-26 सीजन (02 फरवरी, 2026 तक) के लिए, राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता बिक्री से काफी अधिक रही है। विशेष रूप से, 4.97 लाख मीट्रिक टन (छटळ) यूरिया की आवश्यकता के मुकाबले 6.06 छटळ यूरिया उपलब्ध कराया गया, जबकि बिक्री 4.77 छटळ दर्ज की गई । इसी प्रकार, खरीफ 2025 सीजन के दौरान भी 4.37 छटळ की आवश्यकता के मुकाबले 6.07 छटळ यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी ।

गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों तक केवल उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक ही पहुंचें। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत, घटिया उर्वरकों के निर्माण या बिक्री के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान है । अप्रैल 2025 से अब तक, देश भर में दोषियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए 4,11,350 छापे मारे गए हैं, 15,024 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और 783 एफआईआर (ऋक्रम) दर्ज की गई हैं ।

विशेष रूप से तमिलनाडु में, इसी अवधि के दौरान राज्य अधिकारियों ने 20,727 छापे मारे हैं, जिसके परिणामस्वरूप 50 लाइसेंस निलंबित या रद्द किए गए और 5 एफआईआर दर्ज की गईं । सलेम, इरोड, थूथुकुडी, तिरुवरूर और तंजावुर जैसे जिलों में कार्रवाई की गई, जहां नकली यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक जब्त किए गए ।

केंद्रीय क्षेत्र किसान उत्पादक संगठन योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन

भारत सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र

योजना के अंतर्गत अब तक 10,000 एफपीओ गठित किए जा चुके हैं।

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत 10,000 एफपीओ में से 1,175 एफपीओ में शत प्रतिशत महिला सदस्य हैं। एक जनवरी 2026 तक, ह्य10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धनह्न की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत पंजीकृत कुल 56.32 लाख किसानों में से 21.96 लाख महिला किसान हैं।

राजनाथ सिंह और सीएम योगी का मुख्यमंत्री धामी ने किया स्वागत, हरिद्वार कार्यक्रम में हुए शामिल

देहरादून ,(जीएनएस)।

उत्तराखंड में आज वीआईपी मूवमेंट के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज राज्य दौरे पर पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीनों नेताओं का स्वागत किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का स्वागत किया।

रक्षा मंत्री, यूपी सीएम और केंद्रीय मंत्री हरिद्वार स्थित सप्तऋषि मैदान में आयोजित त्रिदिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। यहां महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा

उत्तराखंड के चार धाम वास्तव में भारत की आध्यात्मिक चेतना के आधार हैं। कहा कि पहले रामभक्तों का अपमान होता था तब देश की विरासत का अपमान होता था। अब राष्ट्र की विरासत रामभभक्तों का सम्मान होता है। किसी ने सोचा नहीं था कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर बना और भव्य बना।

अपने गांव पंचूर जाएंगे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव पंचूर जाएंगे। जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर में नवनिर्मित कक्षा कक्षों के लोकार्पण समारोह में भी शामिल होंगे। जनता इंटर कॉलेज चमकोट खाल में योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 9 की पढ़ाई की थी।

पंचूर गांव में जन्मे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय पंचूर, कक्षा 6 से 8 तक जूनियर बिथ्याणी, कक्षा 10 खाड़ी हाई स्कूल नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल, कक्षा 11 एवं 12 भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश जबकि स्नातक की पढ़ाई कोटद्वार महाविद्यालय से की थी।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भुवनेश्वर में आयोजित ब्लैक स्वान शिखर सम्मेलन की शोभा बढ़ाई

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (6 फरवरी, 2026) ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के सहयोग से ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित ब्लैक स्वान समिट, इंडिया की शोभा बढ़ाई।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जब प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है। नए आविष्कार इतनी तेजी से सामने आ रहे हैं कि हमारी प्रणालियां, कौशल और कारोबारी मॉडल अक्सर इनके साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही, ये तीव्र प्रगति साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिमों, डीपफेक, भ्रामक सूचना और प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता सहित कई गंभीर चुनौतियां भी ला सकती हैं। हालांकि, तीव्र तकनीकी परिवर्तनों का नवाचार और विकास पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्लैक स्वान समिट जैसे आयोजनों के माध्यम से, कौशल विकास के द्वारा क्षमताओं को और भी अधिक बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और डिजिटल एवं वित्तीय परिवर्तन को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु नवीन तरीकों का पता लगाया जा सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की वित्तीय प्रणाली एक प्रभावशाली क्रांति की साक्षी रही है। किसानों, छोटे दुकानदारों और महिलाओं के बीच बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल भुगतान बहुत आम हो गए हैं। उनके लिए, "फिनटेक" केवल एक तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि यह उनकी जीवनरेखा बन गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की फिनटेक की कहानी को न केवल प्रौद्योगिकी की गाथा के रूप में, बल्कि महिला-पुरूष समानता आधारित न्याय की गाथा के रूप में भी याद किया जाना चाहिए।

पीएम ने पूर्वी नागालैंड में विकास को बढ़ावा देने वाले ऐतिहासिक समझौते की सराहना की

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्वी नागालैंड के विकास को गति देने वाले एक ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया।

इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा ह्यएक्सह्ल पर साझा किए गए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखाः

'यह वास्तव में एक ऐतिहासिक समझौता है, जो विशेष रूप से पूर्वी नागालैंड के विकास की राह को गति प्रदान करेगा।

जम्मू में जम्मू और कश्मीर पर एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक सम्पन्न

केन्द्रीय गृह मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में आतंकी इको-सिस्टम को खत्म करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की

जम्मू-कश्मीर में हमारे देश के दुश्मन तत्वों द्वारा पोषित आतंकी इको-सिस्टम को मोदी सरकार के समन्वित प्रयासों से लगभग खत्म कर दिया गया है

केन्द्रीय गृह मंत्री ने जम्मू और कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया

बैठक के दौरान सुरक्षा घेरे को और मजबूत करने के लिए इनोवेटिव उपायों पर भी चर्चा की गई

(जीएनएस)।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जम्मू में जम्मू और कश्मीर पर एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक (आई.बी.), थल सेनाध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (उअढऋ) के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में आतंकी इको-सिस्टम को ध्वस्त करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हमारे देश के दुश्मन तत्वों द्वारा पोषित आतंकी इको-सिस्टम को मोदी सरकार के समन्वित प्रयासों से लगभग समाप्त कर दिया गया है।

श्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान सुरक्षा घेरे को और मजबूत करने के लिए इनोवेटिव उपायों पर भी चर्चा की गई।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ३ी-शृ'२३ङ्खल्ल के प्रयासों से आतंकवाद-मुक्त जम्मू और कश्मीर के हमारे विजन को तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए और कदम उठाने के निर्देश दिए।

हरिद्वार में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ-भौगोलिक के साथ संस्कृति की भी सुरक्षा जरुरी, योगी समेत ये वीआईपी भी पहुंचे

(जीएनएस)।

हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र स्थित भारत माता मंदिर परिसर में ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय भव्य समारोह का शुक्रवार को विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर समाधि मंदिर एवं प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया।

तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन में देशभर से संत-महात्मा, धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक नेतृत्व उपस्थित रहा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र चेतना, सनातन संस्कृति, गुरु-शिष्य परंपरा तथा मानव सेवा जैसे विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

समारोह के समापन अवसर पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक तथा जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि महाराज सहित अनेक संत-महात्मा एवं गणमान्य अतिथियों ने गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज के समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पावन अवसर पर

उपस्थित होना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने मां गंगा को नमन करते हुए ऋषि-मुनियों की स्मृतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, किंतु उनकी साधना, विचार और जीवन दर्शन आज भी समाज को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।

प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा उनके जीवन मूल्यों और विचारधारा को पुनः जागृत करने का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हरिद्वार केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है। यहीं से भारतीय संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक जड़ों की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। यदि संस्कृति कमजोर होती है तो राष्ट्र भी कमजोर हो जाता है।

उन्होंने सनातन संस्कृति, अद्वैत वेदांत, भक्ति परंपरा और गुरु-शिष्य संवाद को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिकता और संस्कृति एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कार जुड़ जाएं तो राष्ट्र को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आ'ान करते हुए देश की अखंडता, संप्रभुता और गौरव की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प लेने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज ने आध्यात्मिक साधना को समाज सेवा से जोड़कर एक विशिष्ट जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। भारत माता मंदिर की स्थापना के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक गौरव को मूर्त रूप दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति और विरासत को वैश्विक पहचान मिल रही है तथा उत्तराखंड विकास और विरासत के संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी सनातन परंपरा के सशक्त ध्वजवाहक थे। करुणा, मैत्री और राष्ट्रभक्ति उनके जीवन के मूल मूल्य थे।

सम्पादकीय

भारत ने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनने और साथ ही भारत पर अमेरिकी टैरिफ को कम करते हुए 18 प्रातिशत करने की जानकारी दी। हालांकि इस ट्रेड डील की विस्तृत जानकारी आना अभी बाकी है। लेकिन प्राधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत भारत सरकार के कई मंत्रियों ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। लेकिन विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि इस ट्रेड डील में किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों को नजरअन्दाज किया गया है। इसका जवाब देते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि भारत ने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। गोयल ने कहा कि ट्रेड डील पर अंतिम दौर की बातीत में ब्यौरे तय किए जा रहे हैं और बहुत जल्द भारत और अमेरिका की ओर से इस पर एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। ट्रंप ने दूसरी ओर ट्रूथ सोशल पर को जानकारी दी उसमें कहा गया है कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को जीरा करेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्राधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से अधिक खरीद पर सहमति जताईं है जिसमें 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, वृषि, कोयला और अन्य कई उत्पादों की खरीद शामिल है। इसके बाद अमेरिकी वृषि मंत्री ब्रुक रोलिस ने भी इस डील को अमेरिकी किसानों के लिए लाभदायक बताते हुए कहा कि अमेरिकी वृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच बढ़ने और इसमें 1.3 अरब डॉलर के भारत के साथ अमेरिकी कृषि व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। भारत की चिताओं पर अगर हम नजर डालें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में खेती से क्षेत्र की आधी आबादी यानि करीब 70 करोड़ लोगों का भरण-पोषण हो रहा है और यह सेक्टर भारत की रीढ़ बना हुआ है। खेती भारत के करीब आधे कामगारों को रोजगार देती है। अमेरिका कईं सालों से भारत पर कृषि क्षेत्र को व्यापार के लिए खोलने के लिए दबाव बना रहा है। भारत खाद्या सुरक्षा, आजीविका और लाखों किसानों के हित का हवाला देकर इससे बचता रहा है। भारत और अमेरिका के बीच वृषि व्यापार 8 अरब डालर का है, जिसमें भारत चावल, झींगा और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका मेवे, सेब और दालें भेजता है। अमेरिका अब अपने 45 अरब डालर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए मक्का, सोयाबीन और कपास के बड़े वृषि निर्यात के लिए दरवाजे खोले जाने की मांग करता रहा है। विशेषज्ञों को डर है कि टैरिफ रियायतों को लेकर भारत को अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी और सार्वजनिक खरीद को कम करने के लिए दबाव डाल सकती है। ये दोनों भारतीय किसानों के प्रामुख कवच हैं, जो उन्हें अपनी फसलों को उचित दाम की गारंटी देकर उन्हें कीमतों में अचानक कमी से बचाती है और अनाज खरीद को सुनिाित करती है। दिलचस्प बात है कि भारत के नीति आयोग के एक ताजा दस्तावेज में प्रास्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत चावल, डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सेब, बादाम और जीएम सोया सहित अमेरिकी वृषि आयात पर टैरिफ कटौती की सिफारिश की गईं है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में 'पिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया-भारत' व्यापार केस स्टडी संकलन जारी

(जीएनएस)।

दिल्ली स्थित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में ह्यपिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया-इंडिया: 100 बिलियन डॉलर की साझेदारी के लिए आदर्श स्थितियांह्व शीर्षक से भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार केस स्टडीज संकलन जारी किया गया। इस आयोजन में नीति निमार्ताओं, राजनयिकों, उद्योगपतियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया, जहां दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के अगले चरण पर विचार-विमर्श किया गया।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) और न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप के सहयोग से तैयार किया गया यह संकलन भारत और ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत कंपनियों की वास्तविक व्यावसायिक यात्राओं का संग्रह है। इसमें उन 30 संगठनों की बाजार प्रवेश की कहानियां, विकास रणनीतियां और सीखी गई अहम बातों को शामिल किया गया है, जिन्होंने दोनों बाजारों में अवसरों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है।

वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने इस पहल को अधिक प्रभावी बनाने में आईआईएफटी के प्रयासों की सराहना की और इसे नीति, उद्योग तथा शैक्षणिक हितधारकों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि केस स्टडीज यह दशार्ते हैं कि व्यापार समझौतों ने कैसे नए अवसरों का निर्माण किया है और व्यवसायों ने इनका उपयोग अपनी प्रगति के लिए किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) के फायदों को सुदृढ़ करने और उन्हें आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त श्री फिलिप ग्रीन ओएएम ने इस पहल की सराहना की और द्विपक्षीय व्यापार पर सार्थक संवाद को बढ़ावा देने में आईआईएफटी की भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा, सरकार और उद्योग जगत को एक ही मंच पर लाने वाले ऐसे प्रयास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध स्थापित करने में बेहद महत्वपूर्ण हैं।

संयुक्त सचिव सुश्री पेटल ढिल्लों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों में हो रही प्रगति पर प्रकाश डाला।

उनका कहना था कि आईआईएफटी ने अनुसंधान आधारित जानकारी प्रदान करने और संवाद को सहज बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) को सुदृढ़ करने और इसे अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है।

आईआईएफटी के कुलपति प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी ने वास्तविक व्यावसायिक अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने और उन्हें उद्योग और शिक्षा जगत के लिए शिक्षण संसाधनों के रूप में परिवर्तित करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार की साझेदारियां अनुसंधान और व्यवहार के बीच पुल का निर्माण करती हैं और वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को समर्थन देने के लिए आईआईएफटी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।

ऑस्ट्रेलिया स्थित न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप के संस्थापक और सीईओ, श्री दिपेन रुघानी ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में व्यावसायिक केस स्टडी की अहमियत पर जोर दिया। इसी संस्था की कार्यकारी निदेशक, सुश्री नताशा झा भास्कर ने दोनों देशों के बाजारों में सक्रिय कंपनियों की सफलता की कहानियों और अनुभवों को साझा किया। सत्र का समापन दोनों बाजारों में कार्यरत सरकारी प्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक पैनल चर्चा के साथ हुआ। इसके बाद भागीदारों को नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान किए गए।

राजदूत अनिल वधवा ने केस संकलन की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में हो रहे प्रयासों को देखते हुए, यह संकलन व्यवसायों, नीति निमार्ताओं और शोधकताओं के लिए एक उपयोगी संसाधन सिद्ध होगा। यह न केवल अवसरों की पहचान और चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होगा, बल्कि सफल अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) अपनी स्थापना वर्ष 1963 से ही सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 2002 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त इस संस्थान ने भारत के वैश्विक व्यापार परिदृश्य में मानव संसाधन और ज्ञान संरचना विकसित करने में अहम योगदान दिया है। शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के माध्यम से आईआईएफटी ने भारत के बाह्य व्यापार की संतुलित प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पश्चिमी वायु कमान ने उच्च स्तरीय संयुक्त अभियान सम्मेलन की मेजबानी की

सर्वक्षेत्रीय संयुक्त अभियान (एडीजेओ) अभ्यास 2026 की रूपरेखा

(जीएनएस)।

पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय ने सर्वक्षेत्र संयुक्त अभियान (एडीजेओ) अभ्यास 2026 के ढांचे के अंतर्गत 5 और 6 फरवरी 2026 को उच्च स्तरीय संयुक्त अभियान सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युद्ध के परिचालन स्तर पर अंतर-सेवा और अंतर-सेवा समन्वय को मजबूत करना था, ताकि तेजी से जटिल होते बहु-क्षेत्रीय वातावरण में भारतीय रक्षा बलों की संयुक्त परिचालन क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके। विचार-विमर्श में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (आईडीएस), भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) और रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआईए) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ नेतृत्व ने भाग लिया।

पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी, एयर मार्शल जेएस मान ने अपने उद्घाटन भाषण में समकालीन और भविष्य के संघर्षों में संयुक्तता और एकीकृत युद्ध क्षमता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने वायु, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों में निर्बाध एकीकरण प्राप्त करने वाले सर्वक्षेत्रीय परिचालन दृष्टिकोण की आवश्यकता का उल्लेख किया, जिससे चुनौतीपूर्ण और प्रतिबंधित वातावरण में निर्णायक परिणाम प्राप्त हो सकें। इसके अलावा, उन्होंने सेवाओं के बीच अंतर-संचालनीयता बढ़ाने, क्षेत्र-निरपेक्ष निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, सेंसर से शूटर तक के संबंधों को मजबूत करने और अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने पर बल दिया।

एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने एडीजेओ 2026 सम्मेलन को

संबोधित किया और एकीकृत योजना, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षमता प्राथमिकीकरण के लिए संयुक्त व्यवस्था को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भविष्य की आकस्मिक स्थितियों के लिए व्यापक परिचालन तत्परता को मजबूत करने के लिए सुसंगत अंतर-सेवा प्रतिक्रियाओं और क्षमता अंतराल की संरचित पहचान पर बल दिया। उन्होंने सेवाओं के बीच तालमेल बिठाने और एकीकृत परिचालन परिणाम देने के लिए सर्वक्षेत्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने मजबूत एकीकृत परिचालन क्षमता और सतत रणनीतिक तत्परता के निर्माण के लिए त्वरित सैद्धांतिक विकास और तीनों सेनाओं के संसाधनों के समन्वय का समर्थन किया।

सम्मेलन के समापन पर, पश्चिमी वायु कमान के वायु अधिकारी कमान-इन-चीफ, एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने एक व्यापक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से प्राप्त महत्वपूर्ण सबकों का हवाला देते हुए भविष्य के युद्ध संचालन पर उनके दूरगामी प्रभावों की व्याख्या की। उन्होंने निर्णायक रणनीतिक प्रभाव उत्पन्न करने में वायु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका, आक्रामक हवाई अभियानों के साथ सतही युद्धाभ्यास के समन्वय की अनिवार्यता और स्टैंड-ऑफ हथियारों के उपयोग से प्राप्त रणनीतिक लाभ पर जोर दिया।

एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने 1971 के युग की विशेषता वाले पारंपरिक घर्षण-आधारित मॉडल और प्रभाव-आधारित संचालन ढांचे से हटकर एक अधिक चुस्त, अनुकूलनीय और पूर्णतः एकीकृत संयुक्त युद्ध प्रतिमान की ओर दृढ़ बदलाव का समर्थन किया। उन्होंने मौजूदा क्षमता अंतराल की पहचान करने और उन्हें पाटने, सभी क्षेत्रों में अभिसरण को सुदृढ़ करने और सर्व-क्षेत्रीय युद्धक्षेत्र में समन्वित, प्रभाव-संचालित प्रतिक्रियाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने की अनिवार्यता पर विशेष ध्यान दिलाया।

सर्वक्षेत्रीय संयुक्त अभियान अभ्यास 2026 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के संपूर्ण दायरे में सफलता प्राप्त करने में सक्षम, वास्तव में अंतर-संचालनीय और भविष्य के लिए तैयार संयुक्त बल के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने की संभावना है।

चित्रदुर्ग शहर और आसपास के क्षेत्रों में नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-ट्राई ने दिसंबर 2025 के दौरान कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र- एलएसए में नेटवर्क गुणवत्ता स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट-आईडीटी के निष्कर्ष जारी किए हैं। इसमें शहर/राजमार्गों के मार्ग भी शामिल हैं। बेंगलुरु स्थित ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालय की निगरानी में आयोजित ड्राइव टेस्ट का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों, संस्थागत केंद्रों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और उच्च गति के सडक गलियारों जैसे विभिन्न उपयोग परिवेश में मोबाइल नेटवर्क का वास्तविक प्रदर्शन आकलन करना था।

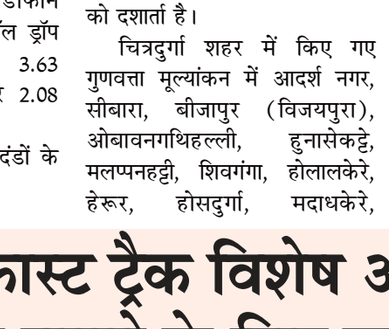

2 दिसंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की टीम ने चित्रदुर्ग शहर और आसपास के 401.2 किलोमीटर क्षेत्र दायरे में विस्तृत परीक्षण किए। इनमें 393.2 किलोमीटर शहरी मार्ग परीक्षण, 13 हॉटस्पॉट और 8 किलोमीटर का पैदल परीक्षण शामिल रहा। परीक्षण में 2जी, 3जी, 4जी और 5जी तकनीकों का मूल्यांकन किया गया। इससे उपयोगकताओं के विभिन्न हैंडसेट क्षमताओं में सेवा अनुभव का पता चला। स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट संबंधी गुणवत्ता परीक्षण के निष्कर्ष सभी संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत करा दिए गए हैं।

मूल्यांकन किए गए प्रमुख मापदंड-

क) वॉइस सेवाएं: कॉल सेटअप सफलता दर (सीएसआर), कॉल ड्रॉप दर (डीसीआर), कॉल सेटअप समय, कॉल साइलेंस दर, स्पीच क्वालिटी (एमओएस) और कवरेज की जांच की गई।

ख) डेटा सेवाएं: डाउनलोड/अपलोड थ्रूपुट (डेटा स्थानांतरण), लेटेंसी (डेटा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में लगने वाला समय या विलंब), जिटर (डेटा पैकेट के पहुंचने के समय में अनियमित बदलाव), पैकेट ड्रॉप दर और वीडियो स्ट्रीमिंग विलंब की जांच की गई।

कॉल सेटअप सफलता दर — एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड और वीआईएल की ऑटो-सिलेक्शन मोड (5जी/4जी/3जी/2जी) में कॉल सेटअप सफलता दर क्रमशः 97.90 प्रतिशत, 79.86 प्रतिशत, 96.77 प्रतिशत और 76.10 प्रतिशत है।

कॉल ड्रॉप दर —ऑटो-सिलेक्शन मोड (5जी/4जी/3जी/2जी) में एयरटेल, बीएसएनएल, आरजेआईएल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की कॉल ड्रॉप दर क्रमशः 0.39 प्रतिशत, 3.63 प्रतिशत, 0.98 प्रतिशत और 2.08 प्रतिशत पाई गई।

प्रमुख सेवा गुणवत्ता मापदंडों के आधार पर प्रदर्शन का सारांश

सीएसएसआर: कॉल सेटअप सफलता दर (प्रतिशत में), सीएसटी: कॉल सेटअप समय (सेकंड में), डीसीआर: कॉल ड्रॉप दर (प्रतिशत) और एमओएस: मीन ओपिनियन स्कोर जो दशार्ता है कि उपयोगकताओं को सेवा की गुणवत्ता कैसी लग रही है। यह सामान्यतः आवाज की गुणवत्ता को दशार्ता है।

चित्रदुर्गा शहर में किए गए गुणवत्ता मूल्यांकन में आदर्श नगर, सीबारा, बीजापुर (विजयपुरा), ओबावनगथिहल्ली, हुनासेकट्टे, मलप्पनहट्टी, शिवगंगा, होलालकेरे, हेरूर, होसदुर्गा, मदाधकेरे, बीरेनहल्ली, हिरियूर, ऐमंगला, क्यादिग्गेरे, कल्लिरोप्पा, विट्ठाला नगर, नंदनहल्ली, मदकारीपुरा, हाइकाल चल्लकेरे, थलाकु, मुस्तुर, बोगलेराहट्टी, जीआर हल्ली, पिल्लेकेरेनहल्ली, आदि जैसे उच्च जनसंख्या या घनत्व वाले क्षेत्र शामिल रहे।

ट्राई ने चल्लकेरे बस स्टैंड, चल्लकेरे तालुक कार्यालय, चित्रदुर्ग जिला अस्पताल, चित्रदुर्ग केएसआरटीसी बस स्टैंड, चित्रदुर्ग आरटीओ कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय चित्रदुर्ग, हिरियुर सरकारी अस्पताल, हिरियूर केएसआरटीसी बस

केंद्रीय सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए

(जीएनएस)।

केंद्रीय सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) में बुनियादी ढांचे का समर्थन करने, डिजिटल केस प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने और निगरानी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं:

1.न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए (सीएसएस) राज्यों के प्रयासों को केंद्रीय प्रायोजित योजना पूरक बनाती है, जिसमें जिला और अधीनस्थ अदालतों सहित एफटीएससी के लिए कोर्ट हॉल, आवासीय इकाइयाँ, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष बनाए जाते हैं। योजना की शुरूआत से उत्तर प्रदेश राज्य को कुल 1,756.41 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है (31.12.2025 तक), जिसमें से वित्तीय वर्ष 2014-15 से 1,205.11 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। 31.12.2025 तक, उत्तर प्रदेश राज्य में 2,923 कोर्ट हॉल हैं।

2. भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के साथ निकट समन्वय में संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से ई-कोर्ट परियोजना चरण-तीन को लागू कर रही है। डिजिटल केस प्रबंधन को मजबूत करने के लिए, सभी कोर्ट परिसरों में केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस) 4.0 लागू किया गया है; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)मामले की जानकारी का सार्वजनिक उपयोग प्रदान करता है; वादी-पक्ष और वकीलों के लिए ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए जस्टआईएस मोबाइल ऐप जैसे इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन उपकरण कार्यरत हैं, जिनके क्रमशः 3,54,86,435 और 22,090 डाउनलोड 31.12.2025 तक हो चुके हैं; डिजिटल कोर्ट्स 2.1 को पेपरलेस कोर्ट्स सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है और यह पायलट कार्यान्वयन के अधीन है। इसके अतिरिक्त, न्यायिक अनुसंधान और विश्लेषण का समर्थन करने के लिए एआई-आधारित उपकरण 'लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट (लेगआरएए)' विकसित किया गया है।

3. एफटीएससी के क्रियान्वन को मजबूत करने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

फाइनल में वैभव का 'महा-तांडव', 175 रनों की पारी से ध्वस्त किए अनगिनत रिकॉड्र्स

हरारे के मैदान पर आज फाइनल के रिजल्ट से पहले ही इतिहास लिखा गया है और इसके लेखक हैं- वैभव सूर्यवंशी! अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इस युवा बल्लेबाज ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का वो हाल किया है जिसे क्रिकेट जगत बरसों तक याद रखेगा।

वैभव ने न केवल 55 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़ा, बल्कि 175 रनों की अपनी पारी के दौरान रिकॉड्र्स की ऐसी झड़ी लगा दी कि दिग्गज भी दंग रह गए।

सिर्फ 55 गेंद में 'गदर' और 175 पर खत्म हुआ तूफान

वैभव ने अपनी पारी की शुरूआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और महज 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने गियर बदला और मात्र 55 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया।

ऐतिहासिक स्कोर: वैभव आखिर में 80 गेंदों में 175 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 15 चौके और 15 गगनचुंबी छक्के जड़े।

उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड ध्वस्त: वैभव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड उन्मुक्त चंद (111) के नाम था, जो उन्होंने 2012 के फाइनल में बनाया था।

ब्रेविस का रिकॉर्ड भी चकनाचूर

इस पारी के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस का एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड मिट्टी में मिला दिया है।

एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के: ब्रेविस ने 2022 के सीजन में

18 छक्के लगाए थे। वैभव ने 2026 के इस एडिशन को 30 छक्कों के साथ खत्म किया है।

फाइनल की एक पारी में सर्वाधिक छक्के: फाइनल मैच की एक पारी में 15 छक्के जड़कर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

व19 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे तेज शतक (ॠ३ी२३ ल४ल्लर्शिरि):

विल मलाजकजुक (ऑस्ट्रेलिया): इन्होंने जापान के खिलाफ मात्र 51 गेंदों में शतक जड़ा था।

वैभव सूर्यवंशी (भारत): इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

कासिम अकरम (पाकिस्तान): इन्होंने साल 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 63 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी।

राज बावा (भारत): साल 2022 के वर्ल्ड कप में राज बावा ने युगांडा के खिलाफ 69 गेंदों में शतक लगाया था।

व19 वर्ल्ड कप फाइनल के सर्वोच्च स्कोर

1. वैभव सूर्यवंशी (भारत): 175 रन (बनाम इंग्लैंड, 2026)
2. उन्मुक्त चंद (भारत): 111* रन (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2012)
3. ब्रेट विलियम्स (ऑस्ट्रेलिया): 108 रन (बनाम पाकिस्तान, 1988)
4. स्टीफन पीटर्स (इंग्लैंड): 107 रन (बनाम न्यूजीलैंड, 1998)
5. मनजोत कालरा (भारत): 101* रन (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2018)

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय : 'श्रमिकों की समृद्धि से देश की समृद्धि होती है': डॉ. मांडविया

डॉ. मांडविया ने कहा, श्रमिक कल्याण सरकार के राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण का केंद्र

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक श्रम सुधारों का मकसद श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और सशक्तिकरण

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ओडिशा के पुरी में भारतीय मजदूर संघ के 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ओडिशा के पुरी में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के अखिल भारतीय त्रिवार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और दोहराया कि श्रमिकों का कल्याण, सम्मान और सुरक्षा राष्ट्रीय विकास के प्रति सरकार की दृष्टि का केंद्र बिंदु है।

डॉ. मांडविया ने कहा, 'मुझे श्रम शक्ति और युवा शक्ति के लिए काम करने का सौभाग्य मिला है। ये दोनों शक्तियाँ भारत की प्रगति की नींव हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी।'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीएमएस न केवल भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, बल्कि विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक है और इसने श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने, देश के कार्यबल के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उन्हें राष्ट्रीय विकास और आर्थिक विकास में भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आर्थिक विकास के लिए श्रमिकों और उद्योग दोनों के समान महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए दोनों के बीच सामंजस्य और सहयोग जरुरी है। उन्होंने कहा कि

सरकार ने इस संतुलन को मजबूत करने, श्रमिकों के लिए कल्याणकारी प्रावधानों और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने और उद्योगों के लिए अनुपालन को सरल बनाने के लिए श्रम संहिता लागू की है। उन्होंने कहा, 'मैं श्रम संहिता का स्वागत करने, श्रमिकों में जागरूकता फैलाने और 15 अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए बीएमएस को बधाई देता हूं। यह जिम्मेदार और रचनात्मक नेतृत्व को दशार्ता है, जो श्रमिकों के हितों को संगठनात्मक हितों से ऊपर रखता है' । श्रम संहिता के सहायक प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने अनिवार्य नियुक्ति पत्र, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर, वार्षिक स्वास्थ्य जांच और खतरनाक उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का उल्लेख किया।

सामाजिक सुरक्षा पहलों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों के लिए कवरेज का विस्तार करने और संस्थागत समर्थन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा घोषित आंकड़ों के अनुसार, लगभग 940 मिलियन लोग अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं और साथ ही उन्होंने साल 2026 तक सामाजिक सुरक्षा कवर को 1000 मिलियन लोगों तक विस्तारित करने के लक्ष्य पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि ईएसआईसी के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अब श्रमिकों के बच्चों के लिए चिकित्सा शिक्षा में आरक्षण उपलब्ध है, जिससे आर्थिक बोझ कम पड़ता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उनकी आकांक्षाएं पूरी होती हैं।

डॉ. मांडविया ने कहा कि बीएमएस ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की वेतन सीमा बढ़ाने, न्यूनतम वेतन पर निर्णय लेने और ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन मामलों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और आने वाले दिनों में श्रमिकों के हित में निर्णय लिए जाएंगे।

उन्होंने कहा, 'देश की प्रगति श्रमिकों के कल्याण से अलग नहीं है। जब श्रमिक समृद्ध होते हैं, तभी देश समृद्ध होता है।'

ह्यनया भारतह्न के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिक कल्याण को अपनी मुख्य प्राथमिकता मानते हुए लगातार आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार श्रमिकों के कल्याण, सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए ईमानदारी से काम करने वाले संगठनों को निरंतर समर्थन देती रहेगी।

डॉ. मांडविया ने सभी हितधारकों से 'राष्ट्र सर्वोपरि' की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मिलकर काम करने का आ'ान किया। उन्होंने कहा, 'हमें सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे, प्रत्येक श्रमिक को आगे बढ़ाना होगा और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए सशक्त बनाना होगा।'

सम्मेलन ने श्रम सुधारों, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक सशक्तिकरण पर संवाद के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसमें देश भर के श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उद्घाटन सत्र में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें बीएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हिरणमय पांड्या, बीएमएस के राष्ट्रीय महासचिव श्री रविंद्र हिमते, एफएनपीआर, रूस के अध्यक्ष श्री सर्गेई चेनोर्गेव, श्री भगैया, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, आरएसएस और सुश्री युकी ओत्सुजी, श्रमिक विशेषज्ञ, दक्षिण एशिया और कंट्री ऑफिस, आईएलओ, नई दिल्ली भी शामिल थे।

'रेल के साथ खेल नहीं' एवं 'मेरा टिकट मेरी शान' अभियान के तहत रतलाम, स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक आयोजित

रतलाम, 06 फरवरी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा टिकट लेकर यात्रा करने के लिए यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने तथा ट्रेनों पर पत्थरबाजी एवं अन्य

रेलवे सुरक्षा बल रतलाम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 250 से 300 बच्चे, शिक्षक एवं यात्री उपस्थित रहे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रेलगाड़ियों पर पत्थरबाजी गई कि रेलगाड़ियों पर पत्थरबाजी करना, अनाधिकृत ट्रैक पार करना, रेलवे लाइन पर पत्थर रखना, वीडियो/रील बनाना तथा बिना टिकट यात्रा करना रेल अधिनियम की

बताया गया कि रेलवे एक राष्ट्रीय संपत्ति है और इसकी सुरक्षा करना तथा नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक

अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से मंडल स्तर पर 'रेल के साथ खेल नहीं' एवं 'मेरा टिकट मेरी शान' अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत दिनांक 06 फरवरी 2026 को रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 04 पर यात्रियों, बच्चों एवं आम नागरिकों को जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

न करने, अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार न करने, रेलवे लाइन पर पत्थर न रखने, वीडियो/रील न बनाने, टिकट लेकर यात्रा करने तथा रेलवन ऐप के उपयोग के संबंध में जागरूक किया गया।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी

विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं, जिनमें जुमार्ना एवं कारावास का प्रावधान है।

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यह संदेश भी दिया गया कि टिकट लेकर यात्रा करना न केवल एक वैध दस्तावेज है, बल्कि यह रेल एवं देश के विकास में नागरिकों का एक महत्वपूर्ण योगदान भी है।

इसके साथ ही लोगों को यह भी

श्री अश्वनी कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य

प्रबंधक श्रीमती हीना केवलरामानी, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री

रामराज मीना सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, यात्री एवं बच्चे उपस्थित रहे।

जनसंपर्क विभाग - रतलाम मंडल

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के अंतर्गत आयोजित रिसर्च सिंपोजियम ने दुनिया भर के एआई विशेषज्ञों को आकर्षित किया

एआई रिसर्च को पॉलिसी और रियल-वर्ल्ड के उपयोग से जोड़ना व्यावहारिक, उत्तरदायी और समावेशी एआई के लिए केंद्रित प्लेटफॉर्म

(जीएनएस)।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के हिस्से के रूप में आयोजित 'एआई और इसके प्रभाव' पर रिसर्च सिम्पोजियम को राष्ट्रीय और वैश्विक रिसर्च कम्युनिटी से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 250 से अधिक शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

एआई रिसर्च को वास्तविक दुनिया की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के करीब लाने के लिए डिजाइन किया गया यह सिम्पोजियम; अनुसंधान, नीति और व्यवहार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगी और भारत तथा विदेश के विविध दृष्टिकोणों को एक साथ लाएगा।

18 फरवरी, 2026 को भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में ग्लोबल साउथ पोस्टर ट्रैक के तहत 30 चयनित पोस्टर, इंडिया फोरम शोकेस से 15 और स्टूडेंट्स शोकेस के तहत 15 पोस्टर प्रदर्शित किए जाएंगे।

इस सिम्पोजियम की परिकल्पना एक इंटरडिसिप्लिनरी फोरम के रूप में की गई है, जो भारत, ग्लोबल साउथ और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रमुख शोधकताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है ताकि वे एआई के प्रभाव पर अपने अग्रणी कार्यों को प्रस्तुत कर सकें, पद्धतियों और साक्ष्यों का आदान-प्रदान कर सकें और सहयोग के नए अवसर बना सकें। वे मानव पूंजी, समावेशन, सुरक्षा और विश्वास, मजबूती, नवाचार, विज्ञान और आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे।

इस सिम्पोजियम में मुख्य रूप से प्लेनरी कीनोट्स और रिसर्च डायलॉग, इंटरनेशनल रिसर्च पैनल और ग्लोबल साउथ रिसर्च और पोस्टर शोकेस होंगे।

प्लेनरी सेशन में प्रतिष्ठित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकताओं के साथ बौद्धिक रूप से प्रेरित करने वाले कीनोट, फायरसाइड चैट और संवाद होंगे। इनमें एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर गहन चर्चा की जाएगी और इसके सैद्धांतिक आधारों, व्यावहारिक अनुप्रयोगों तथा सामाजिक प्रभावों का पता लगाया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पैनल के तहत दुनिया भर के दिग्गज शोधकर्ता संक्षिप्त और केंद्रित प्रस्तुतियाँ देंगे, जिनमें एआई के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व नवाचारों को रेखांकित किया जाएगा। यह सत्र विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों की अत्याधुनिक कार्यप्रणालियों, नए एल्गोरिदम और शानदार एप्लीकेशन को साझा करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा।

ग्लोबल साउथ रिसर्च एंड पोस्टर्स शोकेस के दौरान, ग्लोबल साउथ के छात्रों और सहयोगी टीमों द्वारा तैयार किए गए रिसर्च पोस्टर्स का एक जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। यह सत्र उभरती हुई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, मेंटरशिप के अवसर प्रदान करने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों के नवीन समाधानों को उजागर करने का काम करेगा।

उम्मीद है कि इस सिम्पोजियम के परिणाम स्पष्ट और लागू करने योग्य होंगे, जिससे अनुसंधान संस्थानों और नीति-निमार्ताओं के बीच सहयोग और मजबूत होगा। साथ ही, जिम्मेदार एआई को अपनाने की प्रक्रिया में शोध और अनुसंधान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

रिसर्च सिंपोजियम के बारे में अधिक जानकारी https://impact.indiaai.gov.in/events/research-symposium पर उपलब्ध है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के संबंध में अन्य विवरण, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा, विषयगत फोकस और भागीदारी की प्रक्रिया शामिल है, समिट की आधिकारिक वेबसाइट https://impact.indiaai.gov.in/ पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक हितधारकों को वेबसाइट पर जाने और पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और प्रभावशाली उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस वैश्विक संवाद का हिस्सा बन सकें।

डॉ. पी.के. मिश्रा ने दक्ष नेतृत्व कार्यक्रम के दूसरे बैच का शुभारंभ किया, दक्ष, क्षमता विकास आयोग और स्कोप की एक संयुक्त पहल है

अस्थिर विश्व में भारत के विकास का रणनीतिक स्तंभ बना हुआ है: डॉ. पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव

मिशन कर्मयोगी सार्वजनिक क्षेत्र में आजीवन सीखने की संस्कृति का निर्माण कर रहा है: अल्का मित्तल, सीबीसी

(जीएनएस)।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक प्रमुख नेतृत्व विकास कार्यक्रम, दक्ष (आकांक्षा, ज्ञान, उत्तराधिकार और सद्भाव का विकास) के दूसरे बैच का शुभारंभ सत्र आज नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) और सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) द्वारा मिशन कर्मयोगी ढांचे के अंतर्गत संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।

उद्घाटन समारोह में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के वरिष्ठ प्रमुख शामिल हुए। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा; लोक उद्यम विभाग के सचिव श्री के. मोसेस चलाई; कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव श्रीमती रचना शाह; क्षमता विकास आयोग की अध्यक्ष श्रीमती एस. राधा चौहान; स्कोप अध्यक्ष श्री के.पी. महादेवस्वामी; स्कोप के महानिदेशक श्री अतुल सोबती और क्षमता विकास आयोग की सदस्य (प्रशासन) श्रीमती अलका मित्तल शामिल थीं।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए स्कोप के महानिदेशक श्री अतुल सोबती ने कहा कि दक्ष कार्यक्रम प्रमुखों को आत्मचिंतन, तैयारी और रूपांतरण में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नेतृत्व क्षमता के विकास, रणनीतिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।

कार्यक्रम के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए क्षमता विकास आयोग की सदस्य श्रीमती अलका मित्तल ने दक्ष के स्वरूप और उद्देश्यों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 12 महीने की परिवर्तनकारी नेतृत्व यात्रा के रूप में संरचित है। इसमें डिजिटल शिक्षा, प्रमुख संस्थानों में कक्षा शिक्षण, कार्यकारी कोचिंग, व्यावहारिक शिक्षण परियोजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दक्ष के पहले बैच में सीपीएसई के 73 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जबकि दूसरे बैच में ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन और रसद, खनन और खनिज,

विनिर्माण और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों से 72 प्रतिभागी शामिल हैं।

उन्होंने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया। इनमें आईजीओटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों की व्यापक भागीदारी, कर्मयोगी सप्ताह जैसी पहलों के माध्यम से आजीवन शिक्षा का संस्थागतकरण, कर्मयोगी योग्यता मॉडल का विकास, प्रशिक्षण संस्थानों का प्रत्यायन और भारत केंद्रित केस स्टडीज के राष्ट्रीय संग्रह अमृत ज्ञान कोष का निर्माण शामिल है। सीपीएसई के लिए प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों के रूप में नेतृत्व विकास, योग्यता-आधारित विकास, प्रतिभा गतिशीलता और प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा पर बल दिया गया।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने अपने संबोधन में देश के विकास पथ में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बदलती भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने याद दिलाया कि स्वतंत्रता के बाद देश के औद्योगिक और अवसंरचनात्मक आधार के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने मूलभूत भूमिका निभाई। इससे आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की नींव रखी गई। उन्होंने कहा कि कई दशकों तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारत की विकास रणनीति की रीढ़ रहे हैं।

डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि समय के साथ, वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और आर्थिक सुधारों ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र के प्रभुत्व को लेकर चल रही बहसें अब एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण में तब्दील हो गई हैं। यहाँ प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नवाचार केंद्रीय महत्व रखते हैं। इस बदलते परिवेश में, सीपीएसई से अपेक्षाएँ भी विकसित हुई हैं। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करते हुए अधिक चुस्त-दुरुस्त होकर काम करने की आवश्यकता है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत मुक्त व्यापार समझौतों और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत कर रहा है, ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आर्थिक विकास में, विशेष रूप से अनिश्चितता के दौर में, एक रणनीतिक भूमिका निभाते रहते हैं।

डॉ. मिश्रा ने 2021 की सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति का भी उल्लेख किया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वगीर्कृत किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां निजी उद्यमों की भूमिका बढ़ रही है। वहीं ऊर्जा, रक्षा, अवसंरचना और वित्त जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आवश्यक बने हुए हैं, जहां दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित, स्थिरता और लचीलापन महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम उन बाजारों में भी संतुलनकारी भूमिका निभाते हैं जो हमेशा परिपूर्ण नहीं होते और जहां सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचार शामिल होते हैं।

प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते महत्व पर डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) को प्रौद्योगिकी उन्मुख और नवाचार-संचालित बने रहना चाहिए। उन्होंने भारत के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और यूपीआई, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग में प्रौद्योगिकी को बेहतर ढंग से अपनाने और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और ऊर्जा परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं, जहां राष्ट्रीय विश्वास और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

नेतृत्व और मानव संसाधन पर डॉ. मिश्रा ने कहा कि संस्थाएँ अंततः अपने नेतृत्व की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। उन्होंने विशेष रूप से तीव्र तकनीकी परिवर्तन के युग में निरंतर सीखने, अनुकूलनशीलता और रणनीतिक सोच के महत्व पर बल दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को दक्ष कार्यक्रम का उपयोग करके संगठनात्मक सीमाओं से परे अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने, निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने, सहयोगात्मक रूप से कार्य करने और साझा राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप टीमें बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इससे पहले, लोक उद्यम विभाग के सचिव श्री के. मूसा चलाई ने केंद्रीय उद्यम इकाइयों (सीपीएसई) के आकार और आर्थिक योगदान के बारे में संक्षेप में बताया और जीडीपी सृजन तथा केंद्रीय खजाने में उनके योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक और घरेलू परिवर्तनों के बीच इस योगदान को बनाए रखने के लिए भविष्य के लिए तैयार नेतृत्व का निर्माण आवश्यक है और उन्होंने दक्ष को इस दिशा में एक सामयिक पहल बताया।

क्षमता विकास आयोग के सचिव श्री जगदीप गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। उन्होंने मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया।

दक्ष नेतृत्व कार्यक्रम की परिकल्पना वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार करने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम बनाने के लिए की गई है।

एसीसी बैटरी निर्माण के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन

(जीएनएस)।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना "उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" (पीएलआई एसीसी योजना) का संचालन कर रहा है। इसे मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 50 गीगावॉट की घरेलू उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

पीएलआई एसीसी योजना के दूसरे चरण की बोली के अंतर्गत लाभार्थी फर्म, यानी रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड ने 17.02.2025 को भारी उद्योग मंत्रालय के साथ 10 गीगावाट क्षमता की एसीसी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया। दूसरे चरण के लिए योजना की अवधि 01.07.2025 की निर्धारित तिथि से सात वर्ष है। इसमें से पहले

दो वर्ष प्रारंभिक चरण (उत्पादन पूर्व अवधि) हैं।

पीएलआई एसीसी योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर भारत में आयातित एसीसी पर निर्भरता को कम करना है और इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े उधोगों को भारत में एक प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी सेटअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस योजना में लाभार्थी फर्मों द्वारा उद्धत प्रति किलोवाट-घंटे की सब्सिडी और निमार्ताओं के लिए वास्तविक बिक्री पर अर्जित मूल्यवर्धन के प्रतिशत के आधार पर प्रोत्साहन का प्रावधान है। लाभार्थी फर्मों को निर्धारित तिथि से 2 वर्षों के भीतर (मूल इकाई स्तर पर) कम से कम 25% मूल्यवर्धन प्राप्त करना और निर्धारित तिथि से 5 वर्षों के भीतर इसे 60% तक बढ़ाना सुनिश्चित करना होगा।

यह योजना तकनीकी दृष्टि से निष्पक्ष है और यह सुनिश्चित करती है कि उन्नत तकनीकों को अधिक प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर किए गए व्यय को निवेश मानदंडों को पूरा करने की अनुमति है। इससे वे अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में नवीनतम तकनीक को एकीकृत कर सकें।

यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

उन्नत रसायन विज्ञान कोशिकाओं के लिए पीएलआई योजना

(जीएनएस)।

भारी उद्योग मंत्रालय उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) - "उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" का संचालन कर रहा है। इसे मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 50 गीगावॉट की घरेलू उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

कुल लक्षित 50 गीगावाट क्षमता में से 40 गीगावाट क्षमता चार लाभार्थी कंपनियों को आवंटित की गई है। लाभार्थी कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत 31.12.2025 तक कुल 3,237 करोड़ रुपए का निवेश और 1,118 रोजगारों का सृजन हुआ है।

सरकार की इस पहल ने भारतीय सेल निमार्ताओं को सेल निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। पीएलआई एसीसी योजना के आवेदकों के अलावा, कम से कम 10 निमार्ताओं ने अगले पांच वर्षों में देश में लगभग 178 गीगावॉट की संचयी क्षमता की घोषणा की है। इसके अलावा, पीएलआई एसीसी योजना ने कैथोड सक्रिय सामग्री, एनोड सक्रिय सामग्री, फॉइल आदि जैसे घटकों की मांग को बढ़ाया है। भारतीय निमार्ताओं ने घटक निर्माण और पुनर्चक्रण इकाइयों की घोषणा की है।

भारी उद्योग क्षेत्र में सुधार के लिए वैश्विक साझेदारियाँ

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के साथ भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा साझेदारी (आईजेआईसीपी) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में सहयोग के संबंध में जापानी निमार्ताओं के साथ भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग के क्षेत्रीय दायरे का पता लगाने के लिए बातचीत की है।

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तथा औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को मजबूत करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना - चरण क्क" लागू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 891.37 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 714.64 करोड़ रुपये के सरकारी योगदान वाली 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

इस योजना के अंतर्गत भारी उद्योग क्षेत्र में डिजिटलीकरण को मजबूत करने के लिए एमएचआई ने 4 स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ) केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र हैं: सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 (सी4आई4) लैब पुणे; आईआईटीडी-एआईए फाउंडेशन फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आईआईटी दिल्ली; आई-4.0 इंडिया @ आईआईएससी, बेंगलुरु; और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल, सीएमटीआई, बेंगलुरु।

यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

मुसीबत में फंसे थलपति विजय, मद्रास हाई कोर्ट से झटका, चुकाने होंगे करोड़ो, जानें क्या है मामला

(जीएनएस)।

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आयकर विभाग द्वारा लगाए गए 1.5 करोड़ रुपये के जुमार्ने के खिलाफ दायर उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना है कि जुमार्ना लगाने का आदेश निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारित किया गया था, इसलिए उसमें दखल देने का आधार नहीं बनता।

आयकर मामले में नहीं मिली थलपति विजय को राहत

आयकर विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में थलपति विजय ने कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये की आय का खुलासा नहीं किया था। ये आय फिल्म पुली से जुड़ी बताई गई थी। वर्ष 2015 में विभाग ने थलपति विजय के घर पर छापेमारी की थी, जहां से मिले दस्तावेजों के आधार पर ये आरोप लगाया गया था।

इसी के चलते आयर विभाग ने थलपति विजय पर 1.5 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया है, जिसे चुनौती देने के लिए एक्टर मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे थे। न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने याचिका खारिज करते हुए कहा हैकि जुमार्ना आदेश समय-सीमा के भीतर पारित हुआ है और इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

वकील की दलील और कोर्ट का रुख

हालांकि अदालत ने ये भी स्पष्ट किया है कि थलपति विजय के पास इस आदेश को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती देने का विकल्प मौजूद है। थलपति विजय की ओर से पेश वकील ने आदेश को चुनौती देने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि कानून के तहत अपील का रास्ता खुला है, जिसका उपयोग याचिकाकर्ता कर सकते हैं।

'जन नायकन' के सेंसर विवाद के बीच बढ़ी मुश्किलें

आपको बता दें कि थलपति विजय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' (खंल्ल ठ'ल्ल) के सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। हालांकि ये आयकर मामला फिल्म से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है लेकिन लगातार कानूनी उलझनों ने अभिनेता को सुर्खियों में ला दिया है।

थलपति विजय अब आगे क्या करेंगे?

-मद्रास हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब थलपति विजय के पास अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष जाने का विकल्प है। देखना होगा कि वह इस फैसले को आगे चुनौती देते हैं

केंद्रीय पर्यवेक्षकों को चुनाव आयोग (ईसीआई) की ब्रीफिंग संपन्न हुई

असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आगामी आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा आयोजित केंद्रीय पर्यवेक्षकों की ब्रीफिंग बैठकें आज आईआईआईडीईएम में

संपन्न हुईं।

ब्रीफिंग बैठकें दो दिनों में यानी 5 और 6 फरवरी, 2026 को तीन चरणों में आयोजित की गईं। इन बैठकों में 714 सामान्य पर्यवेक्षकों, 233 पुलिस पर्यवेक्षकों और 497 व्यय पर्यवेक्षकों सहित 1,444 अधिकारियों ने भाग लिया। पर्यवेक्षकों को मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव संचालन और व्यय, सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। उन्हें ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया।

'परीक्षा पे चर्चा' सीएम योगी बोले- पीएम मोदी के शब्दों में लक्ष्य की स्पष्टता और हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में सकारात्मक दृष्टि, लक्ष्य की स्पष्टता और हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना करने की प्रेरणा समाहित है।

लखनऊ, 6 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में सकारात्मक दृष्टि, लक्ष्य की स्पष्टता और हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना करने की प्रेरणा समाहित है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "परीक्षा आत्मविश्वास, अनुशासन और धैर्य की कसौटी होती है। ऐसे क्षणों में सही मार्गदर्शन विद्यार्थियों के मन से भय हटाकर उनमें विश्वास और ऊर्जा भर देता है। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा' के माध्यम से छात्रों से आत्मीय संवाद किया।"

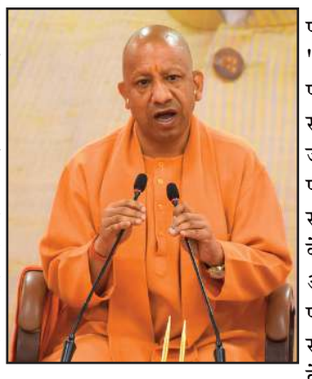

सीएम योगी ने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री ने छात्रों को यह संदेश दिया कि तनाव नहीं, संतुलन को अपनाइए। प्रतिस्पर्धा नहीं, आत्म-विकास पर ध्यान दीजिए और परिणाम नहीं, निरंतर प्रयास पर भरोसा रखिए। उनके शब्दों में सकारात्मक दृष्टि, लक्ष्य की स्पष्टता और हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना करने की प्रेरणा समाहित है।"

उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "यह संवाद केवल परीक्षा कक्ष तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की हर परीक्षा में स्थिर रहने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने सामर्थ्य पर विश्वास बनाए रखने का संदेश देता है। निश्चय ही यह पहल करोड़ों विद्यार्थियों के मन में नई दिशा, नई ऊर्जा और नए विश्वास का संचार करेगी।"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी आभार व्यक्त किया और सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य, आत्मविश्वासपूर्ण प्रयास और सफलता से भरे पथ की शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम का पहला एपिसोड शुक्रवार को जारी हुआ। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने 'आपका स्टाइल-आपकी गति' से लेकर 'लक्ष्य के साथ तैयारी', 'कम प्रेशर-ज्यादा सीखना', 'शोर के बीच टिके रहना' और 'बड़े सपने-बड़े काम' तक अलग-अलग विषयों पर छात्रों से संवाद किया। इसी बीच, उन्होंने छात्रों के कई सवालों के भी जवाब दिए।

पीएम मोदी ने 'मार्क्स, गेम्स और हंसी के बीच बैलेंस' पर भी छात्रों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में पीएम मोदी के सामने गीत और कविता से लेकर बांसुरी बजाने तक छात्रों ने भी कई एक्टिविटी कीं।

लिफ्ट के बहाने लूट करने वाले गिरोह को क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम ने किया गिरफ्तार

(जीएनएस)।

क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम व थाना मड़ियांव और थाना सैरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लिफ्ट देकर भिन्न- भिन्न थाना क्षेत्रों में व्यक्तियों के साथ लूट करने बाले 7 अभियुक्त गिरफ्तार घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की थार कार व 40,130/- रुपए बरामद ! क्राइम ब्रांच व सर्विलास टीम व थाना मडियाव पुलिस टीम व थाना सेरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर की सहयोग से क्राइम टीम ने अपराधियों को धर दबोचा ।दिनांक 01.02.2026 को बादी हृदयनारायण पुत्र श्रीकृष्ण पता ग्राम जाजपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर द्वारा सैरपुर थाने पर सूचना दी गई कि घर जाने हेतु हैडिल चौराहा पर गाड़ी का इंतजार कर रहा था तभी एक काले रंग की थार आयी जिससे 100 रू0 में कानपुर छोडने की बात हुई फिर मै गाड़ी में बैठ गया जिसमें 4 लोग सवार थे जिन्होने मुझे मारा पीटा और मारते पिटते मेरा मुबाइल और जेब में रखे 6,000/- रु० छीन लिये छीनने के बाद रिंग रोड से ले जाकर एक आलू के खेत में मुझे धक्का दे के भाग गये। तहरीर के आधार पर थाना सैरपुर ने मु0सं0 13/2026 धारा 309 (6) बीएनएस पंजीकृत किया गया मुकदमा पंजीकृत होते ही सैरपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम व थाना मड़ियांव

पुलिस हरकत में आई तमाम सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले , सीसीटीवी व मुखबिर की सुचना से क्राइम ब्रांच व सैरपुर पुलिस को सूचना मिली की लूट की घटना को अंजाम देने वाली थार गाड़ी व अभियुक्तगण इन्दौराबाद अण्डरपास से रैथा लोधमऊ किसानपथ होकर घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी से जाने वाले हैं व पुनः आज किसी गंम्भीर घटना घटित करने की फिराक में है !

सूचना मिलते ही मौके पर क्राइम टीम व सर्विलांस टीम व थाना मड़ियांव की टीम रैथा किसान पथ होते हुए लोधामऊ अंडर पास की सर्विस लाइन पर घेराबंदी की पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बिना नंबर प्लेट वाली थार को रोका थार में चालक सहित 4 व्यक्ति सवार थे ईनके पास से 12 बोर का 2 अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस व मोबाईल और 40,130/- रुपए बरामद हुआ

अभियुक्त से पूछताछ व तलाशी लेने पर चोरों ने बताया की थार गाड़ी हम ऋषभ पांडे जस्ट बुक योर कार नाम से ट्रैवल कंपनी से लिया है इसी कार से हम लोग लूटपाट करते हैं लुटे हुए धन में से कार वाले को भी हिस्सेदारी देते हैं थार गाड़ी में बरामद पैसों के बारे में पुलिस ने पूछा तो युवकों ने बताया कि सैरपुर में पंजीकृत लूट के मुकदमे में ₹60000 व मोबाइल लूट थे जिसमें से 25100 रुपए व मोबाइल उसी मुकदमे के है व दिनांक 3/2/2026 को थाना सरोजिनीनगर में लूट किए हैं सोरोजनीनगर से 99901 रुपए और एक मोबाइल मिला था जिसमें से 15030 रुपए बचे हैं इस लूट का भी मामला सरोजनी नगर में दर्ज है इसके अलावा बीकेटी थाना क्षेत्र अंतर्गत 30/1/2025 को एक व्यक्ति से 500 रुपया व मोबाइल लूट थे जो पैसे खर्च हो गए ,गिरफ्तार हुए चोरो की पहचान (1)ऋषभ गोस्वामी पुत्र उदल गोस्वामी उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सेवई थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ (2)अक्षय कुमार पुत्र श्रीकृष्ण रावत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सेवई थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ (3)आलोक पुत्र रामजी लाल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सेवई थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ (4)शुभम पाण्डेय पुत्र सरवन पाण्डेय उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कोडरा थाना सहजनवा जिला गोरखपुर लखनऊ (5)ऋषभ पाण्डेय पुत्र पवन कुमार पाण्डेय निवासी मोहल्ला ठाकुरद्वारा हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी हाल पता

मकान नं095 रुचिखण्ड थाना आशियाना लखनऊ (ट्रवेल एजेंट) (6)ज्ञानी पुत्रः आशाराम उम्र 20 वर्ष निवासी मोहीदीनपुर थाना पी०जी०आई० जनपद लखनऊ (7)रामसफल रावत पुत्र राम जियावन उम्र 30 वर्ष निवासी मोहीदीनपुर थाना पी०जी०आई० जनपद लखनऊ

बरामदगी लूट की घटना में बरामद कुल 40130 रूपया दो मोबाइल दो तमंचा 12 बोर की दो जिंदा कारतूस 12 बोर की और घटना में प्रयोग की गई थार वाहन

गिरफ्तार करने वाली टीम

क्राइम ब्रांच प्रभारिक शिवानंद मिश्र के दिशा निर्देश में काम कर रही काईम टीम उ०नि० नितिन कुमार उ0नि0 शुभम उ०नि०आशुतोष पाण्डेय उ0नि0 राहुल त्रिपाठी उ0नि0 प्रकाश सिंह उ०नि० प्रशान्त मिश्रा उ०नि० असलम खान की अहम भूमिका ।

थाना सैरपुर की टीम

थाना प्रभारी सैरपुर उ०नि० सिद्धार्थ जायसवाल, उ0नि0 अनुज कुमार, उ०नि०अनिल कुमार, उ०नि० अनुराग गोस्वामी,उ०नि० ऋषभ कुमार,क्राइम टीम व एडीसीपी उत्तरी ऋषभ रुणवाल की अहम भूमिका रही।

एमएसडीई की सचिव और एनसीवीईटी की अध्यक्ष श्रीमती देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में एनएसक्यूसी की 45वीं बैठक आयोजित की गई

(जीएनएस)।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की सचिव और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीवीईटी) की अध्यक्ष श्रीमती देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2026 को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस कमेटी (एनएसक्यूसी) की 45वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस कमेटी के तहत उन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनका उद्देश्य देश भर में व्यावसायिक योग्यताओं की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और उन्हें उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाना है।

इस बैठक में एनसीवीईटी के कार्यकारी सदस्य प्रोफेसर (डॉ.) अशोक कुमार गाबा, परिषद के निदेशक एवं सचिव डॉ. सुहास देशमुख और ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों के एनएसक्यूसी सदस्य शामिल हुए। इसके साथ ही, सेक्टर एक्सपर्ट और प्रमुख हितधारक भी बैठक में उपस्थित रहे।

कुल 15 अवॉर्डिंग बॉडीज ने समिति के समक्ष अपनी क्वालिफिकेशन्स प्रस्तुत कीं। बैठक में कुल 80 योग्यताओं पर विचार किया गया, जिनमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राष्ट्रीय संस्थानों के प्रस्ताव शामिल थे। इनमें डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग (डीजीटी), डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्टिलरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी), नेशनल एकेडमी ऑफ फ्वऊएळक इंडियन

नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंट (क्ठ-रढअ3ी) के साथ-साथ विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल के प्रस्ताव शामिल रहे।

ये क्वालिफिकेशन ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी-आईटीईएस, स्वास्थ्य सेवा, लाइफ साइंसेज, एयरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स, निर्माण, विनिर्माण, पर्यटन और आतिथ्य, ग्रीन जॉब्स और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे प्राथमिकता वाले और हाई-ग्रोथ सेक्टर से संबंधित हैं। इसके अलावा, मेडिकल टूरिज्म, असंगठित अर्थव्यवस्था और संबद्ध सेवाओं में कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई और अपडेटेड क्वालिफिकेशन भी शुरू की गई हैं, जिससे विभिन्न शिक्षार्थी समूहों के लिए स्ट्रक्चर्ड स्किलिंग तक पहुंच बढ़ रही है और रोजगार क्षमता में सुधार हो रहा है।

इस बैठक का एक मुख्य आकर्षण विभिन्न प्रमाणन निकायों द्वारा प्रस्तुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित पाठ्यक्रमों को स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस (एसओएआर) पहल के तहत शामिल करने की मंजूरी देना रहा। एसओएआर पहल को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के प्री-इवेंट के रूप में जोड़ा गया है, जो एआई-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य के तैयार कार्यबल को प्रशिक्षित करने पर भारत के फोकस को और मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त, आगामी प्रतियोगिताओं के लिए इंडिया स्किल्स और वर्ल्ड स्किल्स से संबंधित पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी दी गई।

समिति ने परिणाम-आधारित और दक्षता-संचालित डिजाइन, गुणवत्ता के मानकों, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, असेसमेंट की सख्ती और इंडस्ट्री वैलिडेशन पर विशेष जोर दिया। उम्मीद है कि ये स्वीकृत पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को रोजगार के लिए तैयार कौशल और उद्योग-संबंधित प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे। साथ ही, ये कौशल और शिक्षा इकोसिस्टम के भीतर करियर में आगे बढ़ने और अन्य क्षेत्रों में स्विच करने के स्पष्ट अवसर भी सुनिश्चित करेंगे।

बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि भारत में स्किल क्वालिफिकेशन को मजबूत, विश्वसनीय और अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुरूप बनाए रखने में एनएसक्यूसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विचार-विमर्श विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप एक कुशल, अनुकूलनक्षम और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एनएसक्यूसी की 45वीं बैठक में लिए गए निर्णय भारत के स्किलिंग सेक्टर को आधुनिक बनाने के प्रति एनसीवीईटी की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उम्मीद है कि इन फैसलों से एनएसक्यूएफ की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और प्रभाव में और वृद्धि होगी, जो देश भर के युवाओं के लिए बेहतर रोजगार क्षमता और आजीवन सीखने के विस्तृत अवसर प्रदान करने में सहायक होंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हरित हाइड्रोजन अनुसंधान और क्षमता निर्माण में भारत-नीदरलैंड सहयोग सुदृढ किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग- डीएसटी ने स्वच्छ ऊर्जा में भारत और नीदरलैंड के बीच वैज्ञानिक सहयोग बढाते हुए आज भारत-नीदरलैंड हाइड्रोजन फैलोशिप कार्यक्रम आरंभ किया। इस अवसर पर नीदरलैंड के ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय तथा 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों- आईआईटी के बीच हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन अनुसंधान में सक्षम शैक्षणिक सहयोग ढांचा स्थापित करने के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत-नीदरलैंड हाइड्रोजन फैलोशिप कार्यक्रम के आज जारी योजना दिशानिर्देश और प्रस्ताव आ'ान (सीएफपी), राष्ट्रीय क्षमता-निर्माण पहल है जो विभिन्न संस्थानों के योग्य भारतीय डॉक्टरेट, पोस्टडॉक्टरेट और संकाय आवेदकों के लिए खुली है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने भारत में नीदरलैंड के उप राजदूत श्री हुइब मिजनारेंड्स की उपस्थिति में इस फैलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

श्री करंदीकर ने कहा कि हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को अनुसंधान से लेकर स्ै थापन तक बढ़ाने के लिए केंद्रित अंतरराष्ट्रीय सहयोग और लक्षित क्षमता-निर्माण पहल महत्वपूर्ण हैं और यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां प्रदूषण कम करना कठिन है। उन्ै होंने कहा कि यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

नीदरलैंड के उप राजदूत श्री हुइब मिजनारेंड्स ने हाइड्रोजन और ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में भारत-नीदरलैंड सहयोग बढाने पर जोर दिया। ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. जौके डी व्रीस ने वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों से निपटने में निरंतर शैक्षणिक साझेदारी की भूमिका पर बल दिया।

भारत-नीदरलैंड हाइड्रोजन फैलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य नीदरलैंड्स के उन्नत हाइड्रोजन पारिस्थितिकी प्रणालियों के ै यापक अनुभव द्वारा हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में भारत की स्ै थापन तैयारी मजबूत बनाना है। इसमें प्रणाली समेकन, सुरक्षा, तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण, जीवन-काल मूल्यांकन और स्वदेशीकरण के उपायों पर जोर दिया गया है। फैलोशिप का उद्देश्य है कि अनुसंधान के परिणाम राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा प्राथमिकताओं में योगदान दें।

इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की मेजबानी में ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय और 19 आईआईटी के बीच संस्थान- से-संस्थान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए, जिससे हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा अनुसंधान में दीर्घकालिक शैक्षणिक सहयोग के लिए उपयुक्ै त ढांचा स्ै थापित हुआ। यह समझौता ज्ञापन संकाय और छात्रों के आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान और ज्ञान साझाकरण को सुगम बनाएगा जिसमें स्वतः वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता नहीं होगी।

यह उच्च स्तरीय संपर्क भारत और नीदरलैंड की हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान, क्षमता निर्माण और स्ै थापन-उन्मुख नवाचार बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता दशार्ता है, जो भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा स्वतंत्रता 2047 और नेट-जीरो 2070 के उद्देश्यों के अनुरूप है।

वीओसी पोर्ट अथॉरिटी भारत का पहला बंदरगाह बना, जिसने एंटी-ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की शुरूआत की

(जीएनएस)।

समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी एक उन्नत एंटी-ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरूआत करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, जो महत्वपूर्ण बंदरगाह बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस परियोजना में एक व्यापक एकीकृत रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) और रडार-आधारित ड्रोन डिटेक्शन और जैमिंग सिस्टम की तैनाती शामिल है, जो विशेष रूप से जटिल बंदरगाह वातावरण के लिए तैयार की गई है, जो 360-डिग्री कवरेज और सर्वदिशात्मक असर प्रदान करती है। ड्रोन डिटेक्टर, ड्रोन डिटेक्शन रडार और मैन-पैक जैमर मिलकर एक व्यापक सुरक्षा प्रणाली बनाते हैं जो 5 किमी तक की प्रभावी रेंज के साथ सर्वदिशात्मक कवरेज प्रदान करता है। त्वरित तैनाती के लिए डिजाइन किया गया, यह प्रणाली संवेदनशील परिचालन क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाती है और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक प्रति उपाय क्षमता में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रणाली अनधिकृत ड्रोन का वास्तविक समय पर पता लगाने, ट्रैकिंग, वर्गीकरण और निष्प्रभावी करने में सक्षम बनाती है, जिससे रणनीतिक संपत्तियों, कर्मियों और बंदरगाह संचालन की सुरक्षा होती है।

इस परियोजना के लिए समझौते पर औपचारिक रूप से श्री ए. गणेशन, मुख्य यांत्रिक अभियंता, वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी तथा श्री अनुराग अग्रवाल, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) की ओर से हस्ताक्षर किए गए। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।यह समझौता श्री सुशांत कुमार पुरोहित, आईआरएसईई, अध्यक्ष, तथा श्री राजेश सुंदरराजन, आईएएस, उपाध्यक्ष, वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ।परियोजना को अगले तीन महीनों के भीतर पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमृत काल विजन 2047 एवं मैरीटाइम इंडिया विजन (एमआईवी) 2030 के अनुरूप यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री सुदृढ़ता को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य हवाई क्षेत्र की निगरानी को सुदृढ़ करना, उभरते तटीय रक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा बंदरगाह पर आपातकालीन प्रतिक्रिया तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाना है।यह अग्रणी पहल वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी की अगली पीढ़ी की सुरक्षा तकनीकों को अपनाने और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दशार्ती है। इसके कार्यान्वयन के पश्चात, एंटी-ड्रोन प्रणाली बंदरगाह की परिचालन क्षमता और लचीलापन उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगी तथा वीओसी पोर्ट को देश के बंदरगाहों में सुरक्षा नवाचार के लिए एक मानक (बेंचमार्क) के रूप में स्थापित करेगी।

आईआरएसईई के अध्यक्ष सुशांत कुमार पुरोहित ने कहा कि एंटी-ड्रोन प्रणाली की स्थापना बंदरगाह के महत्वपूर्ण समुद्री अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसके सक्रिय और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दशार्ती है। उन्होंने आगे कहा कि उन्नत निगरानी एवं काउंटर-ड्रोन तकनीकों को अपनाने से परिचालन सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ होती है तथा यह बंदरगाह की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।